(d) whether Government would encourage the trade unions to take over the viable sick units and run them on Co-operative lines; and

(e) whether Government have interacted with trade unions on the issue of workers' cooperatives to run viable sick units to avoid closure or retrenchment?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) to (c) 120 PSEs who had adopted the Voluntary Retirement Scheme during the last 4 years to shed surplus manpower have reported that 88,371 persons opted for voluntary retirement. The assessment about the number of employees who would be considered surplus to the requirement of the PSE has to be made by the PSE themselves. The exact number of employees who could be categorised as surplus in each PSE is, therefore, not available; The expenditure which will be incurred by a PSE which has already notified surplus manpower is also required to be assessed by the said PSE having regard to the pay scale in which such employees are working, the actual basic pay and DA drawn by them, the length of service rendered by them in the same organisation and in the previous organisation and the number of months service left before superannuation. When so many factors are evolved it is not possible to work out the average amount payable for workers or to prepare an estimate of the total amount involved to be paid to all the surplus workers.

(d) and (e) The revival of Sick Industrial Companies by workers cooperatives is one of the measures envisaged under the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985. Some Trade Unions have suggested setting up of Workers Cooperatives during the meeting of the Special Tripartite Committee held on 20-1-1992. Government is prepared to consider viable proposals for running sick PSEs through workers' cooperatives where the workers were willing. However, the details in this regard have to be worked out based on specific proposals from workers' cooperatives company-wise.

Tender for transportation work of CCI

3157. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Cement Corporation of India has recently opened a tender No. 11/(16)93-MMO, regarding allotment of transportation work of cement to various destinations;

(b) if so, how many tenders have been invited for price-bid;

(c) how many tenderers, amongst them, were allotted the aforesaid work;

(d) what was the originally quoted rate of the tenderers who have been allotted the work and at what rate the work was allotted;

(e) what was the creditability of the awardee tenderers; and

(f) the names of the tenderers who have not been invited and on what ground?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) Yes, Sir.

(b) Three tenderers, who were prequalified by the Tender Committee, were invited for price-bid opening.

(c) to (f) Since the rates quoted by the tenderers were exhorbitant, the tender was not finalised by CCI and hence no transportation work has been allotted to any of the tenderers.

खोई पर आधारित अखबारी कागज परियोजना का परित्याग किया जाना

3158. **श्री अजीत जोगी :**
श्री मूल चन्द मीणा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में खोई पर आधारित किसी अखबारी कागज परियोजना का परित्याग करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस परियोजना का परित्याग करने के क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) सरकार ने नेपा लिमिटेड द्वारा, अलीगंज, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में, भारत सरकार की बजटीय सहायता से खोई पर आधारित अखबारी कागज की एक मिल लगाने का अनुमोदन वर्ष 1989 में दिया था। नेपा लिमिटेड ने 800 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया और उस पर "साइट कार्यालय" आदि जैसे अवस्थापना कार्य किए। तथापि, धन की कमी के कारण इस परियोजना के आगामी कार्यान्वयन के लिए इसके अधिग्रहण हेतु उद्यमियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए है

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में निवेश

3159. **श्री अजीत जोगी :**
श्री मूल चन्द मीणा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची में कितना-कितना निवेश किया गया है ;

(ख) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड को कितनी-कितनी हानि हुई है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने अधिकारियों ने स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण किया और वर्ष 1993-94 के दौरान कितने अधिकारियों द्वारा स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण किये जाने की संभावना है ;

(घ) इस उद्देश्य के लिये कुल कितनी कितनी धन-राशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ङ) बाकी धनराशि कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एच० ई० सी०) रांची में यथा 1-3-94 को केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(लाख रुपये में)

शेयर पूंजी	27368.35 रुपये
सरकार से अप्रतिभूत ऋण	27110.76 रुपये
कुल :	54479.11 रुपये

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में निजी क्षेत्र द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया है।

(ख) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड को वर्ष 1990-91, 1991-92 व 1992-93 में क्रमश 99.51 करोड़ रुपए, 192.65 करोड़ रुपए व 127.25 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है।

(ग) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम 22.10.90 को शुरू की गई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में कोई मामला स्वीकार नहीं किया गया। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम के अंतर्गत स्वीकार किए